गोरखपुर से प्रकाशित

RNI Reg. NO. UPBIL/2023/87841

साप्ताहिक

स्वदेशी इनक्रेडिबल

Web:www.sinews.in/E-mail: info@sinews.in

सिर्फ सच के साथ...

वर्ष : 02 अंक : 16 गोरखपुर रविवार 6 अक्टूबर 2024 पृष्ठ : 8 मूल्य 02 रूपया

आजमगढ़ मंडल को भी योगी सरकार ने बनाया

रूरल टूरिज्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा

एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने प्रदेश में रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में एक नए अध्याय को जोड़ा है। प्रदेश की समृद्ध ग्रामीण परिवेश को घरेलू व विदेशी पर्यटकों में प्रसिद्ध बनाने की परियोजना से अब आजमगढ़ मंडल को भी जोड़ा जा चुका है। सीएम योगी के विजन अनुसार योजना के अंतर्गत, आजमगढ़, मऊ व बलिया में 4 गांवों में रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे समेत विभिन्न पर्यटक सुविधाओं विकास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आजमगढ़ मंडल के गांवों को इस योजना के साथ जोड़ने के बाद अब कुल मिलाकर रूरल टूरिज्म के लिए डेवलप किए जा रहे गांवों की संख्या 97 हो गई है। देवीपाटन, चित्रकूट, अयोध्या, लखनऊ तथा वाराणसी मंडल में पहले से ही इस परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वयन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि प्रदेश के अन्य मंडलों के चिह्नित गांवों को भी इस प्रक्रिया से जल्द ही जोड़ा जाएगा। इन सभी पर्यटन विकास एवं निर्माण कार्यों को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सीएम योगी के विजन अनुसार पूरा किया जा रहा है और योजना को गति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पर्यटन विभाग द्वारा योजना को दी जा रही गतिसीएम योगी के विजन अनुसार, परियोजना के अंतर्गत आजमगढ़, मऊ और जौनपुर जिलों में कुल 4 गांवों का चयन रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे परियोजना के लिए चयनित किया जाएगा। सभी चारों गांव में एक विलेज को ऑर्डिनेटर, एक–एक जिला को ऑर्डिनेटर, एक टूरिज्म एक्सपर्ट, एक रूरल डेवलपमेंट एक्सपर्ट व टीम लीड की तैनाती होगी। प्रत्येक गांव में 10 लोकल गाइड, 5 स्टोरी टेलर, तथा लोकल कुजीन का स्वाद उपलब्ध कराने का दायित्म 5 परिवारों को सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त, जरीदोजी, मूंज, लकड़ी के शिल्पकार, कुम्हार तथा बोटिंग, फिशिंग, फल व सब्जी तोड़ने तथा साइक्लिंग इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 कलाकारों तथा स्थानीय लोगों को कार्यभार सौंपा जाएगा। ग्राम स्तर पर 10 होम स्टे तक निर्मित किए जा सकेंगे। इनकी रजिस्ट्रेशन, विकास व नियमन इत्यादि की प्रक्रिया को स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की पॉलिसी के अनुरूप पूरा किया जाएगा। सारी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के दिशा–निर्देशन में पूरी की जाएगी। परियोजना के अनुसार, सभी रूम स्टे निधि प्लस पोर्टल के साथ भी एकीकृत होंगे। इसके अतिरिक्त, 4 आइसोलेटेज एग्रो टूरिज्म प्रॉपर्टीज के विकास की संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा। परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक तीन महीने में गांवों में

टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। साथ ही, इन सभी ग्रामों का सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर अकाउंट बनाकर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। ग्रामों में 15 रूम तक की कैपेसिटी पर रूम स्टे विकसित किए जाएंगे। सारी विकास प्रक्रिया को 6 महीने के 3 चरण, 4 महीने के चौथे चरण तथा 2 महीने के पांचवें चरण के रूप में 24 महीनों यानी दो वर्षों की अवधि में विकसित किया जाएगा। पर्यटन बढ़ाने की अपार संभावनाओं में ग्रामीण पर्यटन करेगा इजाफा उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटकों के लिहाज से देश का नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन के अतिरिक्त प्राकृतिक, वन्य व लोक पारंपरिक कलाओं आधारित पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति और प्रकृति को देखने और उसे अनभूत करने की ललक न केवल देसी बल्कि विदेशी पर्यटकों में भी बहुत है।

हरियाणा बीजेपी को लगा बड़ा झटका, अशोक तंवर की घर वापसी, राहुल गांधी ने कांग्रेस में शामिल कराया

एजेंसी

हरियाणा। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दिन भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अशोक तंवर की एक बार फिर से घर वापसी हुई है। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस में शमिल कराया। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि अशोक तंवर हिसार से लोकसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ राजनीतिक मतभेद के कारण उन्होंने 5 अक्तूबर 2019 को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूटी ब्लॉगर मालविका सीतलानी के तलाक के पीछे की वजह आई सामने अरबपतियों की सरकार चलाते हैं पीएम मोदी, में बोले राहुल गांधी, विचारध ाारा की लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस के शेरइसके बाद अशोक तंवर आप में शामिल हुए। आप ने उन्हें हरियाणा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था। वह इससे खुश नहीं थे। इसके बाद उन्होंने आप छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उन्हें सिरसा से टिकट दिया था। वे हार गए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका देते हुए नीलोखेड़ी (सुरक्षित) सीट से पार्टी उम्मीदवार अमर सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। सिंह ने पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि केवल कांग्रेस ही भाजपा सरकार को हरा सकती है जो "किसानों, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रही है।"

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अचानक सोनिया गांधी से मिली

कुमारी सैलजा, 30 मिनट तक चली मुलाकात

एजेंसी

हरियाणा। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुमारी शैलजा ने दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक यह मुलाकात 30 मिनट तक चली है। सोनिया गांधी से मिलने के लिए कुमारी शैलजा अकेले ही 10 जनपथ पहुंची थीं। यह मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि कुमारी सैलजा के चुनाव प्रचार शुरू करने के बाद भी पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से उनकी नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप के साथ पकड़ा गया नेता, बीजेपी ने पूछा मोहब्बत की दुकान में और क्या क्या है? हालांकि, दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने शैलजा को एकजुट रहने और भविष्य में अहम भूमिका मिलने का आश्वासन दिया होगा। राज्य में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। खबरों के मुताबिक, कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खेमे को प्रमुखता मिली है। वह करीब दो हफ्ते तक चुनाव प्रचार से भी दूर रहीं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्तक्षेप के बाद शैलजा ने प्रचार किया। हरियाणा में कांग्रेस बनाएगी अगली सरकार, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा बोले– झूठ की दुकान बन गई है भाजपाहाल ही में राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा दोनों से हाथ मिलवाया और एकता का संदेश दिया। इससे पहले यह बताया गया था कि राज्य में कांग्रेस के अभियान का वास्तविक चेहरा रहे हुड्डा की टिकटों के आवंटन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी, उन्होंने पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए 90 उम्मीदवारों में से अपने वफादारों के लिए 72 टिकटें हासिल कीं। दूसरी ओर, कांग्रेस में हुड्डा की प्रतिद्वंद्वी के रूप में जानी जाने वाली शैलजा अपने समर्थकों के लिए सिर्फ नौ टिकट ही हासिल कर सकीं और 11 सितंबर को उम्मीदवार घोषित होने के बावजूद हिसार जिले के नारनौंद से अपने करीबी डॉ. अजय चौधरी के लिए।

पुलिस स्टेशन में रात भर मचा रहा ड्रामा

सुबह बीजेपी नेता रूपा गांगुली को किया गया गिरफ्तार

एजेंसी

नयी दिल्ली। भाजपा नेता रूपा गांगुली को बांसड्रोनी पुलिस स्टेशन परिसर में रात भर के विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और लाल बाजार ले जाया गया है। पार्टी ने उनकी हिरासत की पुष्टि करते हुए कहा कि गांगुली अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रही थीं। आपको बता दे कि बुधवार को सुबह महालया में बांसड्रोनी में एक पे लोडर ने नौवीं कक्षा के एक छात्र की हत्या कर दी। इसके बाद यहां पर बवाल मच गया। यह क्षेत्र युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। दिन भर माहौल गरम रहा। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन–पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थिति को संभालने के लिए पाटुली थाने के ओसी को मौके पर जाना पड़ा। उन्हें आक्रोशित निवासियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। एक कांस्टेबल को कथित तौर पर थप्पड़ और मुक्का भी मारा गया। पे–लोडर की चपेट में आने से एक स्कूली छात्र की दुखद मौत के बाद पूरा इलाका रणक्षेत्र जैसा हो गया। इलाके के निवासियों ने स्थानीय प्रशासन और इलाके के पार्षद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पे लोडर में भी तोड़फोड़ की गयी। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति की सूचना मिलने पर पाटुली थाने की पुलिस वहां पहुंची। आक्रोशित निवासियों ने पुलिस पर हमला करने का भी आरोप लगाया। इलाके के पार्षद के मौके पर नहीं आने से आक्रोश की आग और तेज हो गयी।दोपहर बाद स्थिति शांत हुई। पार्षद के क्षेत्र में नहीं आने से गुस्सा भड़क गया। दोपहर बाद अचानक स्थानीय निवासियों पर बाहरी हमले के आरोप लगे । मामला फिर गरमा गया। तब डीसी एसएसडी विदिशा कलिता स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में गईं। घटना के बाद स्थानीय बीजेपी नेता रूबी दास ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इसने नये सिरे से उत्साह जगाया। बीजेपी नेता रूपा गंगोपाध्याय ने बीजेपी नेता की रिहाई और दोषियों की गिरफ्तारी की

मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बीजेपी नेता रूबी मंडल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रात भर बांसड्रोनी पुलिस स्टेशन में बैठी रहीं रूपा गांगुली रूपा गंगोपाध्याय यह सवाल उठाते हुए रात भर बांसड्रोनी पुलिस स्टेशन में बैठी रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को बचाने के लिए तृणमूल के गुंडे रास्ते पर आ गये हैं।

सीएम सिद्धारमैया की कम नहीं हो रही मुश्किलें, अब सबूत नष्ट करने का लगा आरोप, शिकायत दर्ज

एजेंसी

कर्नाटक। शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले को लेकर चल रहा विवाद तेज हो गया है। विवाद की वजह से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज की गई है, जिससे एमयूडीए में कथित अनियमितताओं को लेकर उनकी जांच बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री पर अब घोटाले से संबंधित सबूतों को नष्ट करने, उनके प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के बारे में चिंताएं बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। सिद्धारमैया के खिलाफ केस पर भड़की कांग्रेस, कहा– प्रतिशोध की राजनीति कर रही भाजपाइस बीच, कथित मुदा घोटाले में मुख्य शिकायतकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा गुरुवार को गवाही देने और जांच से संबंधित रिकॉर्ड जमा करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुईं। सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ शुरू की गई जांच में मदद के लिए कृष्णा को ईडी के बेंगलुरु जोनल कार्यालय में बुलाया गया था। ईडी ने सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बी को 14 स्लॉट के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों पर 30 सितंबर को एक एफआईआर के बराबर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। लोकायुक्त पुलिस ने 27 सितंबर को कृष्णा की शिकायत पर उनके, राष्ट्रपति, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने को सरेंडर किए 14 प्लॉट, सीएम बोले– वह नफरत की राजनीति का शिकार हुई हैं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) के भूखंड आवंटन मामले में लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को महात्मा गांधी का उद्धरण देते हुए कहा कि ''अंतरात्मा की अदालत'', सभी अदालतों से ऊपर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि गांधीजी के जीवन और विचारों ने उन्हें उनके ''वर्तमान संघर्ष'' में साहस, शक्ति और उम्मीद दी है।

बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नए बापू टावर का उद्घाटन किया। राजधानी के गर्दनीबाग इलाके में स्थित बापू टावर में एक गैलरी है, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन, गतिविधियों और विचारों के साथ–साथ बिहार के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के मंत्रियों विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और जयंत राज के साथ टावर के निचले तल, तीसरी और पांचवीं मंजिल का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, "नई पीढ़ी इस टावर का भ्रमण कर बापू, उनके विचारों और उनके आदर्शों को जान सकेगी।

ब्राह्मण होकर नॉन वेज खाते थे सावरकर, कर्नाटक के मंत्री का बिवादित बयान, पोते रंजीत और भाजपा का पलटवार

एजेंसी

कर्नाटक। कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने वीर सावरकर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने वीर सावरकर को बीफ खाने वाला बताया, जो न सिर्फ बीफ खाते थे बल्कि उसका प्रचार भी करते थे। कांग्रेस नेता ने मोहम्मद अली जिन्ना का भी जिक्र किया। श्गांधीज असैसिनरू द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के कन्नड़ संस्करण के पुस्तक विमोचन को संबोधित करते हुए दिनेश गुंडू राव ने कहा कि यदि हम चर्चा के साथ यह कह सकें कि सावरकर जीतते हैं, तो यह सही नहीं है। वह मांसाहारी थे और वह गोहत्या के खिलाफ नहीं थेय वह चितपावन ब्राह्मण थे।कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सावरकर वैसे तो आधुनिकतावादी थे लेकिन उनकी मौलिक सोच अलग थी। कुछ लोगों ने कहा कि वह गोमांस खाते थे और वह खुलेआम गोमांस खाने का प्रचार कर रहे थे, इसलिए सोच अलग है। लेकिन गांधीजी हिंदू

धर्म में बहुत विश्वास रखते थे और उसमें रूढ़िवादी थे लेकिन उनके कार्य अलग थे क्योंकि वे उस तरह से लोकतांत्रिक थे। सभा में कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री ने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी कहाय उन्होंने कहा कि जिन्ना सावरकर के विपरीत धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे। जिन्ना भी कट्टर इस्लामी आस्तिक थे, लेकिन वे सूअर का मांस खाते थे। जैसा कि लोग कहते हैं, नवप्रवर्तन सिद्धांत के बाद, जिन्ना कट्टरपंथी नहीं थेय वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना चाहते थे और एक अलग देश चाहते थे। पोते रंजीत और भाजपा का पलटवारबीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। भारत वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर सावरकर से कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं सीखा। धारा 370 कांग्रेस पार्टी ने दी थी। यह जवाहरलाल नेहरू की भूल थी और हजारों लोग मारे गये।

हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने वाले सरकारी कर्मियों को ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री माने जाएंगे गैरहाजिर योगी सरकार का बड़ा आदेश

एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश सड़क सुरक्षा अभियान के तहत दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी विभागों के कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार्मिकों पर सख्ती बरती जाएगी। उन्हें दफ्तर में एंट्री नहीं दी जाएगी और गैरहाजिर माना जाएगा। 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जारी हुआ आदेशबता दें कि बुधवार से शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह फरमान जारी किया गया है। मुख्य सचिव

मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सड़क हादसों में बढ़ती मौतें चिंता का विषय हैं। लोगों को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत इसके बारे में जागरूक करके हादसों में कमी लाई जा सकती है। ऐसे में सरकारी विभागों के कार्यालयों में भी हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार्मिकों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय श्रमिकों की आंखों देखी : चारों तरफ धमक की आवाज

बाहर देखा तो मिसाइलें गिर रहीं, लगा सब खत्म हो जाएगा

लखनऊ संवाददाता। इस्राइल में सेवा दे रहे भारतीय श्रमिकों ने वहां चल रहे युद्व की खौफनाक कहानी को कहानी सुनाई। श्रमिकों ने कहा, इस्राइल सरकार ने सतर्क रहने की सलाह दी है। दिन मंगलवार और रात के 10 बजे थे। चारों तरफ धमाके की आवाज सुनाई दे रहीं थीं। खिड़की से छिपकर बाहर देखा तो आसमान से मिसाइलें गिर रहीं थीं और लोग जोर–जोर से चिल्ला रहे थे, मानों खौफनाक मंजर शुरू होने वाला हो। शुक्र है, इस्राइल की तकनीक सुरक्षा इतनी मजबूत है कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही चकनाचूर कर दिया। आवाज में डर का खौफ लिए मंजीत शर्मा ने मोबाइल फोन के माध्यम से अमर उजाला से हुई बातचीत में यह जानकारी दी। लखनऊ के ऐशबाग निवासी मंजीत शर्मा इस्राइल में भारतीय श्रमिक के रूप में सेवा दे रहे हैं। मंजीत शर्मा ने बताया कि बुधवार को घर पर बात हुई और यहां के बारे में जानकारी दी है। परिवार में भय का माहौल जरूर है, लेकिन सब ठीक होने की बात कही है। इस्राइल सरकार की ओर हर तरह की मदद दी जा रही है। भारतीय दूतावास की ओर से भी संदेश भेजा जा रहा है कि सतर्क रहें। भारतीय श्रमिकों के अनुसार, इस्राइल सरकार ने भारतीयों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली है। घबराने की जरूरत नहीं है, यहां सभी सुरक्षित हैं।

सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही वीडियो खौफनाक

इस्राइल पर ईरान ने बीते दिनों मिसाइलों से हमला किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम लोगों तक पहुंच रही हैं। हर दस मिनट में धमक की आवाज आ रही है। चारों तरफ से सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। यह मंजर न केवल इस्राइल निवासियों के लिए बल्कि वहां रह रहे भारतीय श्रमिकों के लिए भी भयावह है।

पिता के देहांत के दौरान भी नहीं हो सके वापस

अप्रैल महीने में इस्राइल पहुंचे। एक सप्ताह बीते ही थे कि घर से पिता के देहांत होने की खबर आई, लेकिन स्थितियों को देखते हुए घर नहीं आ सके। ईरान के हमले से इस्राइल में भय का माहौल है। संदेश के माध्यम से अपील भी कर रही है कि बिना वजह बाहर न जाएं। परिवार से बातचीत हुई, डर जरूर है, लेकिन सुरक्षित होने की जानकारी दी है। – सौरभ गुप्ता, मलिहाबाद, लखनऊ

बंकर में रहने की दी गई है सलाह इस्राइल तकनीक स्तर पर बहुत मजबूत है। ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। बीते दिनों के हमले से डर का माहौल जरूर है, लेकिन यहां के लोगों के लिए यह सामान्य बात है। जगह–जगह पर बंकर (एक रक्षात्मक सैन्य स्थान, जहां बम या अन्य हमलों

से बचा जा सके) बनाया गया है और सायरन बजते ही बंकर में रहने की सलाह दी गई है। – मुकेश सिंह, जानकीपुरम, लखनऊ

हर दस मिनट में सायरन बजता है

एक रात में करीब 70 फायर और मिसाइलें दागी गईं। ईरान की ओर से अभी भी हमला जारी है। रात के समय मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से हर 10 मिनट में सायरन की आवाज सुनाई देती है। यह संकेत है कि किसी तरह का हमला होने वाला है इससे पहले सतर्क होने की सलाह दी जाती है। हालांकि, ईरान के हमले से अभी तक किसी भी भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्घटना नहीं हुई है।

यूपी : केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया बयान

69 हजार शिक्षक भर्ती में दूर होनी चहिए आरक्षण में अनियमितता

लखनऊ संवाददाता। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना को लेकर सपा–कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कराई जानी चाहिए।

अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता को दूर करने के साथ ही जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में शामिल हुए पिछड़े व दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। वहीं, जातीय जनगणना को लेकर कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को बराबर उठाती रही है। हालांकि उन्होंने अब तक जातीय जनगणना न कराए जाने को लेकर कांग्रेस और सपा को जिम्मेदार ठहराया। अनुप्रिया बुधवार को राजधानी के चारबाग स्थित रवींद्रालय प्रेक्षागृह में आयोजित पार्टी की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने जातीय जनगणना के सवाल पर कहा कि जनगणना की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसलिए उनकी पार्टी की मांग है कि जनगणना की प्रक्रिया में जातीय जनगणना की जानी चाहिए। इस संबंध में पार्टी एनडीए की बैठकों में अपना पक्ष रख चुकी है। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस और यूपी में सपा की कई बार सरकार रही है, लेकिन सत्ता में रहते हुए इन दोनों दलों को कभी भी जातीय जनगणना की याद नहीं आई। जातीय जनगणना को लेकर दोनों दलों का नया–नया प्रेम है। बिहार में सरकार ने चाहा तब जातीय

जनगणना कराई। वैसे ही सपा को यूपी में कराना चाहिए था। सभी 10 सीटों पर जीतेंगे एनडीए प्रत्याशीअनुप्रिया ने कहा कि उपचुनावों में एनडीए सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगा। अपना दल (एस) का एक–एक कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी की जीत के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर अपना दल (एस) जिलास्तरीय कार्यक्रम करेगी। भावुक हुई अनुप्रियाकार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अनुप्रिया अपने पिता डॉ. सोनेलाल पटेल को याद कर भावुक हो गईं। डॉ. सोनेलाल की मृत्यु के बाद रवींद्रालय में आयोजित शोकसभा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि तब मैं एक बेटी के रूप में आई थीं। उस वक्त पार्टी के नेताओं ने पार्टी की बागडोर सौंपी थी। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा कि पार्टी परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है।

विद्यार्थियों को कम व्यावहारिक लग रहा चार वर्षीय स्नातक

लखनऊ। विद्यार्थियों को चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के फायदे कागज पर अधिक और व्यवहार में कम नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि प्रवेश प्रक्रिया बीतने की कगार पर है लेकिन अभी तक लखनऊ विवि से संबद्ध कॉलेजों में चौथे वर्ष में प्रवेश के लिए कोई आवेदन नहीं आया है। लखनऊ विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला संस्थान है। ऐसे में यहां इसकी सफलता और छात्रों में रोचकता को लेकर उम्मीदें ज्यादा हैं। लविवि और संबद्ध कॉलेजों में चौथे वर्ष में दाखिले का यह पहला सत्र है। स्नातक चौथे वर्ष की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को पीएचडी में सीधे प्रवेश देने का दावा किया गया, लेकिन अभी तक यह व्यवहार में नहीं आया है। पीएचडी में सिर्फ दो वर्षीय परास्नातक डिग्रीधारकों को ही दाखिला मिल रहा है। यूजीसी की ओर से भी अभी तक इस बारे में कोई भी स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। पीएचडी ही नहीं अभी तक किसी भी नौकरी की अर्हता में भी चार वर्षीय स्नातक डिग्री को शामिल नहीं किया गया है। विद्यार्थी ही नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इन संशोधनों का इंतजार है। यही वजह है कि अभी तक स्नातक चौथे वर्ष में दाखिले के लिए विद्यार्थियों में रुचि नहीं दिखाई दे रही है।

डिलीवरी बॉय हत्याकांड : मुख्य आरोपी ने बाराबंकी कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस की तीन टीमें खाक छानती रह गई

लखनऊ संवाददाता। अभी भी इंदिरा नहर में एसडीआरएफ की टीम भरत की तलाश में जुटी है। नहर से सटे थाना क्षेत्रों से भी संपर्क कर जानकारी साझा की है। डिलीवरी बॉय भरत कुमार प्रजापति 32 हत्याकांड का मुख्य आरोपी गजानन दुबे उर्फ दुबे बुधवार को बाराबंकी कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया। पुलिस की तीन टीमें खाक छानती रह गईं। अब चिनहट पुलिस उसको कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी। उधर अभी भी इंदिरा नहर

में एसडीआरएफ की टीम भरत की तलाश में जुटी है। नहर से सटे थाना क्षेत्रों से भी संपर्क कर जानकारी साझा की है। चिनहट सतरिख के सविता विहार निवासी भरत 24 सितंबर को एक लाख रुपये के कीमत के दो मोबाइल डिलीवर करने के लिए इलाके में गए थे। इस दौरान मोबाइल और कैश लूटने के बाद गजानन दुबे और उसके साथी आकाश शर्मा ने भरत की हत्या कर दी थी। शव बैग में भरकर बाराबंकी में माती में जाकर इंदिरा नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इंस्पेक्टर चिनहट अश्विनी चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी गजानन पर बाराबंकी के कुर्सी थाने में अमानत में खयानत की धारा का केस वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था। वारदात को अंजाम देने के बाद इसी केस में बुधवार को सरेंडर कर दिया।

हरियाणा में कांग्रेस बनाएगी अगली सरकार

हरियाणा। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला बोला। एक सभा को संबोधित करते हुए, हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा झूठ की दुकान बन गई है, जिस क्षण से वह अपना दैनिक संचालन शुरू करती है, नफरत और भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं बेचती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रचार अच्छा चला। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन में लहर है। उन्होंने आगे कहा कि 36 बिरादरी तय करेगी कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि दलित कांग्रेस के साथ हैं जो उनके लिए असली पार्टी है भाजपा पर हमला करते हुए भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उसके पास मुद्दों की कमी है, उनके पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है...यह एक विफल सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में 10 वर्षों तक शासन किया है।

सम्पादकीय

अन्याय का बुलडोजर

शीर्ष अदालत ने एक उस विवादास्पद मुद्दे पर स्पष्ट राय देश के सामने रखी है जिसकी तार्किकता को लेकर पिछले कई वर्षों से बार–बार सवाल उठ रहे थे। यानी कुछ राज्य सरकारों के बुलडोजरी न्याय को लेकर। खासकर भाजपा शासित राज्यों में गंभीर अपराधों व अनधिकृत कब्जों के खिलाफ पीला पंजा चलता देखा गया। जाहिरा तौर पर इस तरह की कार्रवाई न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। सवाल यह भी है कि जब तक किसी व्यक्ति पर सिर्फ आरोप ही लगे हैं, तो उसका घर कैसे गिराया जा सकता है? इस विवादास्पद कार्यशैली को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवायी के दौरान देश की शीर्ष अदालत ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। अदालत का मानना था कि भले ही कोई व्यक्ति किसी संगीन मामले में दोषी हो तो भी बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके मायने अवैध निर्माण को संरक्षण देना कदापि नहीं है। दरअसल, इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से दलील दी जाती रही है कि जिन मामलों में यह कार्रवाई की गई वे गैरकानूनी कब्जे कर किए गए अनधिकृत निर्माण थे। निस्संदेह, ये दलीलें मामले में जरूरी प्रक्रिया को न अपनाये जाने के चलते न्याय के अनुरूप नहीं ठहराई जा सकती हैं। दरअसल, हाल के वर्षों में कई बार देखने में आया कि कुख्यात अपराधियों,हत्यारों व बलात्कारियों के घर जमींदोज कर दिए गए। सतही तौर पर कहा जाता रहा है कि ऐसे अपराधियों में शासन–प्रशासन का भय होना चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई को व्यापक अर्थों में देखें तो यह न तो कानून की कसौटी पर खरा उतरती है और ना ही इसे मानवीय दृष्टि से सही कहा जा सकता है। यही वजह है कि गाहे–बगाहे राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों द्वारा ऐसी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाये जाते रहे हैं। निश्चय ही किसी सभ्य समाज में ऐसे सवालों का उठना लाजिमी है। सर्वोच्च न्यायालय के उस तर्क से सहमत हुआ जा सकता है जिसमें कहा गया था कि किसी मामले में आरोप लगने के बाद ऐसी कार्रवाई कानून सम्मत नहीं है। लेकिन ऐसी कार्रवाई तब भी नहीं की जानी चाहिए जब उसका अपराध साबित हो गया हो। निस्संदेह, घर एक पारिवारिक इकाई का नाम है। एक घर को बनाने में एक व्यक्ति की पूरी उम्र लग जाती है। फिर परिवार के तमाम सदस्यों का भी तो वह घर होता है। उनको अपराधी या आरोपी व्यक्ति के कृत्यों के चलते बेघर तो नहीं ही किया जा सकता। यह न केवल कानून के विरुद्ध है बल्कि अमानवीय कदम भी है। जिनका किसी अपराध से लेना–देना न हो, उन्हें दंडित करना अन्याय ही तो है। फिर यदि किसी व्यक्ति के घर पर आरोपों के चलते बुलडोजर चला दिया गया हो और वही व्यक्ति कालांतर आरोपमुक्त हो जाए, तो ध्वस्त घर बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? शासन–प्रशासन के अधिकारियों को अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के बजाय विवेक व न्यायसंगत तरीके से कोई निर्णय लेना चाहिए। निस्संदेह, अतिक्रमण का संकट देशव्यापी है, जिसे धर्म–जाति से परे कानून की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बल्कि तमाम तरह के अतिक्रमणों को बढ़ावा देने में राजनेताओं की बड़ी भूमिका होती है। कालांतर वोट बैंक बनाने के लिये वे इन अवैध निर्माणों को वैध बनाने की कोशिश में जुट जाते हैं। बहरहाल, देश में अतिक्रमण हटाने और बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर देशव्यापी दिशा–निर्देश तय होने चाहिए। जिससे राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिये इस कार्रवाई को तार्किक ठहराने की कोशिश न कर सकें। साथ ही अवैध निर्माण गिराने की प्रक्रिया सबके लिये एक समान होनी चाहिए। वैसे तो अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया निरंतर सालभर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका चुनाव या लक्षित समय में उपयोग करना गलत होगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं ताकि पूरे देश में बुलडोजर के इस्तेमाल के बाबत तार्किक व एकरूपता वाले दिशा–निर्देश राज्य सरकारों को दिए जा सकें। सवाल अधिकारियों का अपनी विश्वसनीयता कायम करने का भी है।

गेमिंग से जुड़े क्षेत्र में जॉब के शानदार विकल्प

अशोक जोशी

पुरानी कहावत है– पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आजकल इस कहावत के मायने बदल चुके हैं। अब न तो पढ़ने वाले नवाब बनते हैं और न ही खेलने वाले खराब होते हैं। आजकल मैदान पर खेलने से ज्यादा ध्यान युवा ऑनलाइन गेम्स पर दे रहे हैं। ऐसे में कंप्यूटर पर गेम कंसोल तेजी से प्रगति करते जा रहे हैं। कंप्यूटर पर ऑनलाइन गेम खेलने वालों की बाढ़ सी आ गई है जिसने इस क्षेत्र में गेम बनाने वालों के लिए प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित कर दिया है। इससे कंप्यूटर गेम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कैरियर निर्माण के कई विकल्प खुल गये हैं। आज लोग घर के अंदर बैठकर दोस्तों के साथ सीओडी, जीटीए, फीफा, पबजी जैसे गेम खेलते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर पर गेम खेलने से जुड़ी तकनीक को डिजिटल गेमिंग कहा जाता है। अगर आपको भी ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है, तो आप इस फील्ड में गेम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का कोर्स कर शानदार कैरियर बना सकते हैं।

गेमिंग इंडस्ट्री में स्कोप

गेमिंग इंडस्ट्री का विकास तेज़ी से हो रहा है। ग्लोबल गेम्स मार्केट में मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री की हिस्सेदारी लगभग 50 फीसदी तक है और गेमिंग एप्स दुनिया की तीसरी सबसे लोकप्रिय एप केटेगरी है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2026 तक भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री देश को लगभग 23 हजार करोड़ का राजस्व देगी। ऐसे में हमारे देश में भी अब गेम डिजाइनिंग और गेम डेवलपमेंट बेहतर कैरियर ऑप्शन्स के तौर पर उभर रहे हैं। वहीं इससे युवाओं को ऐसे गेम्स तैयार करने का मौका मिलता है जो खेलने वालों को उनके प्ले–स्टेशन्स या ऑनलाइन/वीडियो गेम्स में व्यस्त रखें। इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक युवा गेम डिजाइनिंग से गेम डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग तक, गेमिंग इंडस्ट्री में कई फ़ील्ड्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त प्रशिक्षण और आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश में कई गेम डिजाइन और डेवलपमेंट के कोर्सेज उपलब्ध हैं। उक्त कोर्स करने के बाद आप किसी कंपनी में 4 से 5 लाख रुपए का का शुरुआती सालाना पैकेज ले सकते हैं। इसके बाद अनुभव और टैलेंट के दम पर प्रतिमाह लाखों रुपये वेतन हासिल कर सकते हैं।

कई विकल्प हैं मौजूद

गेम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करना मुश्किल प्रोसेस माना जाता है। इसमें कई प्रोफेशनल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। किसी भी गेम को तैयार करने के लिए कई प्रोसेसेज फॉलो की जाती हैं, जिसके कारण यहां जॉब हमेशा मौजूद रहती है। यहां पर आप एक्शन, स्पोर्ट्स, फेंटेसी आदि कई किस्म की गेम्स तैयार कर शानदार कैरियर बना सकते हैं। कोरोना के बाद से भारत के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री ने बूस्ट किया है। जिससे गेमिंग फैंस को जॉब के विभिन्न अवसर मिले हैं। यहां पर आप गेम डिजाइनर, गेम प्रोड्यूसर, एनिमेटर, ऑडियो प्रोग्रामर, ग्राफिक प्रोग्रामर और गेम राइटर जैसे जॉब प्रोफाइल पर कार्य कर सकते हैं।

आवश्यक योग्यताएं

गेम डेवलपमेंट और डिजाइन कोर्सेज के लिए पात्रता मानक चुने गए कोर्स और इंस्टीट्यूट के मुताबिक अलग–अलग हो सकते हैं। मसलन, गेम डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट लेवल कोर्स करने के लिए किसी भी विषय में 10वीं पास करना जरूरी है लेकिन डिप्लोमा या ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज करने के लिए आपको किसी भी विषय में अपनी 12 वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम पास करना होगा। मास्टर डिग्री कोर्स के लिए, किसी टेक्निकल फील्ड में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इस क्षेत्र में अच्छा कैरियर बनाने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होना जरूरी है क्योंकि गेमिंग और डेवलपमेंट का सारा दारोमदार कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग पर आधारित है।

अगर आप सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें आपको गेमिंग में सर्टिफिकेट कोर्सेज, गेम आर्ट एंड डिजाइन में सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। आप गेम डिजाइन और इंटीग्रेशन में डिप्लोमा, गेमिंग एंड स्पेशल इफ़ेक्ट में डिप्लोमा, गेम आर्ट एंड 3डी गेम कंटेंट क्रिएशन में एडवांस्ड डिप्लोमा, गेम आर्ट में प्रोफेशनल डिप्लोमा, एनीमेशन में डिप्लोमा जैसे कोर्स कर सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन के लिए ग्राफिक्स, एनीमेशन और गेमिंग में बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस और गेम डेवलपमेंट में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल फिल्ममेकिंग और एनीमेशन में बैचलर ऑफ आर्ट्स और एनीमेशन गेम डिजाइन और डेवलपमेंट में बैचलर ऑफ साइंस कोर्स कर सकते हैं।

अतिरिक्त स्किल्स व क्षमताएं

गेम डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में कैरियर बनाने के लिए युवाओं में कुछ खास स्किल सेट का होना जरूरी है। वहीं काफी धैर्य और लगन चाहिए। इनोवेशन, क्रिएटिविटी होने के साथ गेम्स क्रिएट करने, प्रोफेशनल स्किल्स सीखने और गेम डेवलपमेंट प्रोसेस आना चाहिए। केवल क्रिएटिव ग्राफ़िक्स डिजाइन करने या कोड की कुछ लाइन्स लिखने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कंबाइंड एफर्ट और कंप्यूटर साइंस/प्रोग्रामिंग, क्रिएटिव राइटिंग और ग्राफ़िक डिजाइनिंग सहित कई विषयों की जानकारी।

महत्वपूर्ण कोर्सेज

ढेरों इंस्टीट्यूट्स आजकल गेम डेवलपमेंट और डिज़ाइन में प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जिनमें कई सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स, मास्टर लेवल कोर्सेज उपलब्ध हैं। जिनमें गेमिंग में सर्टिफिकेट कोर्सेज, गेम आर्ट एंड डिजाइन में सर्टिफिकेट कोर्स, गेम डिजाइन और इंटीग्रेशन में डिप्लोमा,गेम आर्ट में प्रोफेशनल डिप्लोमा, एनीमेशन, गेमिंग एंड स्पेशल इफ़ेक्ट में डिप्लोमा,गेम आर्ट एंड 3डी गेम कंटेंट क्रिएशन में एडवांस्ड डिप्लोमा गेम प्रोग्रामिंग में एडवांस्ड डिप्लोमा, डिजाइन और डेवलपमेंट एप्लीकेशन में एडवांस्ड डिप्लोमा,ग्राफ़िक्स, एनीमेशन और गेमिंग में बैचलर ऑफ़ साइंस,डिजिटल फिल्म मेकिंग और एनीमेशन में बैचलर ऑफ़ आर्ट्स, गेम आर्ट एंड डेवलपमेंट के साथ मल्टीमीडिया एंड एनीमेशन में इंटीग्रेटेड एमएससी, गेम डिज़ाइन और डेवलपमेंट में एमएससी तथा मल्टीमीडिया और एनीमेशन में मास्टर ऑफ़ साइंस जैसे कोर्सेज शामिल हैं। पढ़ाई के लिए प्रमुख संस्थानमाया एकेडमी ऑफ एडवांस्ड सिनेमैटिक (एमएएसी) मुंबई, ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स बैंगलोर, आई पिक्सियो एनिमेशन कॉलेज बैंगलोर, भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे, एरिना एनिमेशन नई दिल्ली, एनीमास्टर एकेडेमी दृ कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस इन एनिमेशन बैंगलोर।

लगातार बारिश से सड़कें हुईं लबालब, घरों में घुसा पानी

संवाददाता–गोरखपुर। लगातार तीसरे दिन जारी बारिश से जन जीवन बुरी तरह प्रभावित है। तमाम निजी विद्यालयों ने जलभराव और बारिश को मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों में अवकाश की सूचना सुबह ही अभिभावकों को भेज दी। दूसरी ओर जलभराव से उफाएं बड़े नालों के कारण बिलंदपुर, बेतियाहाता पानी की टंकी के पीछे, बुद्धनगर, गोपालापुर समेत कई मोहल्लों में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। इलाहीबाग में बड़ा नाला की दीवार बारिश के पानी के दबाव में क्षतिग्रस्त हो गई है। मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, विजय चौक, धर्मशाला बाजार, बिछिया ताड़ी खाना, पादरीबाजार शताब्दीपुरम, रामजानकीनगर, एचएनसिंह चौराहा, बडगो, शिवपुर साहबाजगंज आदि क्षेत्रों में भी सड़कों से लेकर गलियों तक में काफी जलभराव है।

बारिश के कारण गोपलापुर दाउदपुर मलिन बस्ती, इंदिरानगर, शिवाजीनगर, सर्वोदय नगर और विवेकपुरम में भी जलभराव से लोगों को मुश्किल हुई। नौसढ़ के जवाहर चक और नौसढ़ चौराहे के पास काफी जलभराव है। उधर बिछिया ताड़ीखाना से हनुमान मंदिर रोड पर सड़क पर पानी से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोहनापुर में भी लगातार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। शिवपूजन स्कूल के पास की कच्ची सड़क दल–दल में तब्दील हो गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोसनगर और ग्रीन सिटी फेज 2, खाले टोला, रानीडीहा और अरण्य बिहार, नंदानगर में गोकुलपुरम कॉलोनी, सैनिक कुंज, वसुंधरानगर, स्वर्ण सिटी, प्रज्ञापुरम, कमलेश्वरपुरम, गोरक्षनगर, श्रवण नगर सरीखी नई कॉलोनियों में जलभराव से जन जीवन प्रभावित हुआ। स्पोर्ट्स कॉलेज रोड से सटे गणेशपुरम, गायत्रीपुरम, हरिद्वारपुरम, रामजानकीनगर आदि कॉलोनियों में कई स्थान पर जलभराव है। उधर मेडिकल कालेज रोड के भेड़ियागढ़, विष्णुपुरम कॉलोनी, ओमनगर, बशारतपुर, अशोकनगर, राप्तीनगर डॉक्टर्स इंक्लेव, राप्तीनगर चरगावा में भी जलभराव की समस्या हुई। बिछिया पीएसी पुल के पास गोड़धोईया नाले का डायवर्जन शुक्रवार को ही तोड़ दिया गया था। कुछ एक स्थानों पर शेष बचे डायवर्जन शनिवार को नाला में बढ़े पानी के दबाव के कारण तोड़ दिए गए।

शनिवार की सुबह से ही जलभराव वाले क्षेत्रों में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह, दुर्गेश मिश्र, शिवपूजन यादव, मुख्य अभियंता संजय चौहान समेत अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता सड़क पर उतर आए। सेम्पवेल, पम्पिंग स्टेशन और अस्थाई और स्थाई रूप से जलभराव वाले स्थानों पर लगाए गए पम्प को निरंतर चलाते रहने के निर्देश दिए गए। सफाई कर्मियों से बारिश के बीच नाले में फंसी गंदगी जो प्रवाह को बाधित कर रही थी निकलवाया। सिक्सलेन निर्माण वाले मोहल्लों में कई स्थान पर जेसीबी लगा कर सिक्सलेन नाला निर्माण के दौरान अवरुद्ध किए गए नाले के हिस्से को खोला गया। लगातार तीसरे दिन जारी बारिश से मूंगफली, मूंग, उड़द और तिल जैसी अन्य खरीफ फसलों को भारी क्षति पहुंची है। अगल बगल के खेतों में भी पानी भरा है। किसानों को समझ नहीं आ रहा कि इन खेतों से पानी भी कैसे निकाले? वहीं धान की फसल जिनमें बालियां आ गई थी बारिश और तेज हवा के कारण गिर गई हैं।

उड़ीसा में पलटी बस, सिद्धार्थनगर के दो लोगों की मौत, पांच घायल

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। इटवा थाना के सिकरी गांव से उड़ीसा के धार्मिक स्थलों का दर्शन करने जिस बस पर सवार को होकर सात लोग गए थे वह उड़ीसा के जलेश्वर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह में वापसी के समय पलट गई। दुर्घटना में सिकरी गांव के दो लोगों की मौत हो गई जबकि पांच घायल हो गए। बस में सवार बलरामपुर जिले के भी दो लोगों की मौत हो गई और दस घायल हो गए। घायलों को उड़ीसा के जिला अस्पताल बालासोर में भर्ती कराया गया है। मौत की खबर परिजनों को मिली तो वह लोग उड़ीसा के लिए रवाना हो गए।

तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए डुमरियागंज से 18 सितंबर को रवाना हुई थी। बस में इटवा थाना क्षेत्र के सिकरी गांव से भी सात लोग रवाना हुए थे। उड़ीसा के जलेश्वर थाना के एसआई चिरंजीव राउत के अनुसार तीर्थ यात्रियों की बस थाना क्षेत्र में ही एक स्थान पर पलट गई। बसके चारों पहिए ऊपर हो गए थे। बस में विभिन्न जिलों के 57 लोग सवार थे। वह लोग बाबा भुनेश्वर नाथ, कोर्णाक, जगन्नाथपुरी की यात्रा कर लौट रहे थे। बस पलटने से सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र के सिकरी गांव निवासी राम प्रसाद (55) पुत्र मोती यादव व संतराम (53) पुत्र सुनरपाती की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में इसी गांव के राम लौटन (56) पुत्र श्रीराम, सुभावती (54) पत्नी राम लौटन, राम कृपाल (65) पुत्र राम कलप, फूलमती (65) पत्नी राम कृपाल व सुमिरता (58) पत्नी राम प्रसाद यादव घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल बालासोर में चल रहा है। दुर्घटना बलरामपुर जिले के भी लोगों की मौत हो गई जबकि दस घायल हो गए हैं। दुर्घटना की खबर के बाद मृतकों व घायलों के परिजन उड़ीसा के लिए रवाना हो गए हैं।

उड़ीसा के मंदिरों पर दर्शन करने बस से गए राम प्रसाद की बस पलटने से मौत हो गई है। उनकी पत्नी सुमिरता घायल हैं। उनका इलाज जिला अस्पताल बालासोर में चल रहा है। डुमरियागंज के बस मालिक राजन ने बताया कि पंडा बाबा लोगों के माध्यम से बस की सीटें बुक की जाती हैं। हम से किराए पर ली जाती है। यात्रियों का डिटेल पंडा बाबा के पास होता है। बस को बुक कराने तीन लोग आए थे सभी का मोबाइल बंद आ रहा है। मौके पर मैं खुद जा रहा हूं। इटवा थानाध्यक्ष श्री प्रकाश यादव ने बताया कि सुबह में उड़ीसा से बस दुर्घटना की खबर आई थी। इटवा क्षेत्र के दो लोगों की मौत व पांच के घायल होने की सूचना है। मृतक के परिजनों को तत्काल सूचना दे दी गई थी।

एसटीएफ की रडार पर चाइनीज लहसुन आपूर्ति से जुड़े भारतीय तस्कर

संवाददाता–बहराइच। सेहत के लिए घातक चाइनीज लहसुन की सीमा पार से हो रही आपूर्ति पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। प्रतिबंधित लहसुन की दबे पांव भारतीय क्षेत्र में खेप लाने व भेजने वाले तस्करों की तलाश तेज हो गई है। बहराइच समेत सीमा से लगे जिलों की मंडियों की भी निगरानी हो रही है। हालाकि बरामद लहसुन के सैंपल कस्टम विभाग ने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। भारत में वर्ष 2014 से ही चाइनीज लहसुन प्रतिबंधित है। किड़नी व लीवर के लिए घातक अवयव पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इसके आयात पर रोक लगा दी है। पिछले दो माह से सुनियोजित तरीके से नेपाल के निर्यातक तस्करों के माध्यम से प्रतिबंधित लहसुन को सीमा पार रुपईडीहा, श्रावस्ती के भिनगा व बलरामपुर जिले में आपूर्ति कर रहे हैं। कैरियरों के माध्यम से सीमा से लगे गुप्त गोदामों में डंप किया जा रहा है।यहां से शहर, लखनऊ, दिल्ली समेत कई महानगरों की मंडियों में तस्कर थोक विक्रेताओं के जरिए भेज रहे हैं। एसटीएफ ऐसे लोगों की तलाश कर रही है, जो नेपाली तस्करों से मिलकर भारतीय क्षेत्र में प्रतिबंधित लहसुन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। मंडियों पर भी एसटीएफ की टीम लगातार निर्यातकों पर नजर रख रही है। कस्टम विभाग के मुताबिक अब तक लगभग चार हजार कुंतल चाइनीज लहसुन बरामद किया गया है। जिसको एसएसबी व पुलिस ने पकड़ा है। कस्टम इंस्पेक्टर बृजेंद्र लाखड़ा ने बताया कि यह लहसुन घातक होने की वजह से जांच कराया जा रहा है।

एसएसबी व पुलिस ने बरामद किए गए चाइनीज लहसुन से जुड़ी जानकारी एसटीएफ को साझा किया है। सीमा से लगे तस्करों व कारोबारियों के गुप्त गोदाम भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गोदामों से भोर करीब तीन से चार बजे के समय लहसुन को लोड कर दूसरे जिलों में भेजने का काम हो रहा है। चाइनीज लहसुन के बाजार में उतारने को लेकर तस्कर यूं ही जोखिम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि नेपाल में 120 से 140 रुपये की दर से बिकने वाला चाइनीज लहसुन भारतीय क्षेत्र में 200 से लेकर 225 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। लगभग दोगुने दाम पर बिक्री होने की वजह से तस्करी पर रोक नहीं लगा पा रही है। बरामद लहसुन को कस्टम के हवाले कर दिया गया है। प्रयोगशाला जांच में स्वास्थ्य के लिए घातक होने पर लहसुन को नष्ट किया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित लोगों से 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। हलांकि जिन लोगों के पास से लहसुन बरामद किया गया है, ज्यादातर वे नेपाल के निवासी हैं।

कस्टम के अधिकारी ने बताया कि पूर्व में हुई जांच में कई तथ्य ऐसे सामने आए जो चाइनीज लहसुन के प्रतिबंध का कारण बने हैं। इनमें शरीर के लिए जरूरी एलिसिन कंपाउंड नहीं पाया जाता है। यह टॉक्सिक भी होता है,जो भारतीय लहसुन से अलग करता है। दिनेश धमीजा, कस्टम सुपरिटेंडेंट, रुपईडीहा ने कहा कि प्रतिबंधित लहसुन के चार सैंपल प्रयोगशाला जांच को भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर लहसुन व जिन लोगों से बरामद किया गया है, उन पर कार्रवाई होगी।

गैंगस्टर की जब्त जमीन पर ही मनबढ़ों ने कर दी प्लाटिंग, प्रशासन में मचा हड़कंप

संवाददाता–गोरखपुर। मनबढ़ युवकों के कारनामे अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं। गैंगस्टर एक्ट में डीएम के आदेश पर तहसील प्रशासन ने जिस भूमि को जब्त कर बोर्ड लगाया था, मनबढ़ों ने उसपर प्लॉटिंग कर दी। यही नहीं, तहसील प्रशासन की ओर से लगवाए गए बोर्ड को भी हटवा दिया।जेल से छूटने के बाद गैंगस्टर एक्ट में पाबंद आरोपी भू–माफिया ओमप्रकाश पांडेय ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की तो हड़कंप मच गया। डीएम ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, मोहद्दीपुर के रहने वाले ओमप्रकाश पांडेय पर भूमि बेचने का झांसा देकर ठगी करने का कई केस दर्ज होने के बाद कैंट थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। थानेदार की रिपोर्ट पर डीएम ने ओमप्रकाश के मकान और भूमि के साथ ही सभी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। मोहद्दीपुर स्थित मकान को सील करने के बाद तहसीलदार सदर ने एक मई 2023 को महादेव झारखंडी टुकड़ा–2 दो में स्थित ओमप्रकाश के हिस्से की 54 डिसमिल भूमि को जब्त किया था।

कस्टोडियन बनाए गए तहसीलदार सदर ने डुगडुगी पिटवाकर आसपास के लोगों को कार्रवाई की जानकारी देने के साथ ही मौके पर बोर्ड भी लगवाया था। जमानत पर छूटे ओमप्रकाश पांडेय ने तहसील प्रशासन से शिकायत की कि बोर्ड हटाकर मोहल्ले छह मनबढ़ों ने वहां प्लॉटिंग कर दी। तहसील प्रशासन के जरिए शिकायत डीएम तक पहुंची। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई तो आरोपियों ने निर्माण कार्य बंद कर दिया। अब तक जांच में पता चला कि ओमप्रकाश ने जमीन खरीदने में जो चौहद्दी दिखाई थी, उसी चौहद्दी पर दूसरे को भी जमीन बेची गई है।

डीएम गोरखपुर कृष्णा करुणेश ने बताया की मामले की जांच कराई जा रही है। एक ही चौहद्दी पर दो लोगों को जमीन बेचने का मामला सामने आया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पारदर्शिता से होगा हर काम, मरीज को मिलेगा बेहतर इलाज –एम्स निदेशक

संवाददाता–गोरखपुर। एम्स के नए कार्यकारी निदेशक डॉ. अजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्यों में पारदर्शिता, कठोर अनुशासन को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। इससे एम्स के नाम को और बेहतर किया जा सकता है। नए निदेशक ने कहा कि बीते कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं। उससे एम्स की छवि पर कुछ बट्टा लगा है। पहली प्राथमिकता यही है कि एम्स गोरखपुर की छवि को समाज में बेहतर किया जाए। इसके लिए एम्स में किए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता सबसे प्रमुख हथियार है। लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए मरीजों के बेहतर इलाज का इंतजाम किया जाएगा। एम्स उच्च चिकित्सा शिक्षा का स्थल है। यहां मरीजों को उच्च मानक व गुणवत्ता का इलाज मिले। छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले। उच्च स्तरीय रिसर्च हो। इसके लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थान में अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके साथ ही शनिवार को अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की जाएगी।

सेवा पखवाड़ा के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित

संवाददाता–गोण्डा। नगर के कन्हैया लाल इण्टर कॉलेज में शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा उपाध्यक्ष अर्जुन प्रसाद तिवारी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 02 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत शनिवार को कन्हैया लाल इंटर कालेज में स्वच्छता अभियान चलाया गया एवं अमर शहीद सरदार भगत सिंह की जयंती भी मनाई गई।

साथ ही पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें रौनक वर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने पेंटिंग प्रतिभागियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मेजर राजाराम ने सभी अध्यापकों एवं बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है।

भारत भूमि हमारी माता है और हम सभी इसके आंचल में पल बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इसे स्वच्छ रखें तथा स्वच्छ रखने के लिए लोगों को जागरूक भी करें। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक शिव कुमार पाठक ने किया।

दुर्गा पूजा का चंदा मांगने को लेकर बवाल, घर में घुसकर लूटपाट का आरोप

संवाददाता–देवरिया। थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव में शनिवार को दुर्गा पूजा का चंदा मांगने को लेकर जमकर बवाल हो गया। गांव के कुछ किशोर चंदा वसूली कर रहे थे, इसी बीच पड़ोस गांव से एक युवक पिकअप लेकर पहुंचा। किशोरों ने चालक से चंदा मांगा तो वह गाली–गलौज करने लगा। आरोप है कि चालक गाड़ी से नीचे उतरकर एक किशोर की पिटाई कर दिया। इसके बाद सभी लड़के मिलकर चालक की भी पिटाई कर दिए। उधर, घटना के बाद चालक अपने गांव सझवलिया चला गया और कुछ ही देर में गांव से सैकड़ों लोगों को लाठी–डंडे के साथ लेकर मझवलिया गांव पहुंच एक परिवार के घर पर धावा बोल दिया। घर पर मौजूद महिलाओं को धक्का दे हमलावर घर में घुसकर खूब उत्पात मचाएं। महिला ने घर में घुसकर लूटपाट करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव निवासी श्रवण माली का बेटा आनंद माली शुक्रवार को अपने अन्य दोस्तों के साथ गांव के सड़क पर खड़ा होकर दुर्गा पूजा का चंदा वसूली कर रहा था।

इसी दौरान पड़ोसी गांव सझवलिया का चालक ओमप्रकाश यादव पिकअप लेकर वहां गया। लड़कों ने पिकअप रोककर चंदा मांगा तो वह गाली गलौज करने लगा। इसके बाद उसने आनंद माली को मारपीट कर घायल कर दिया। इससे नाराज लड़को ने चालक की भी पिटाई कर दी।

बौखलाया चालक गांव जाकर बड़ी संख्या में गांव वालों को लेकर आनंद के घर आ पहुंचा और घर पर मौजूद मां इंदू देवी और बहन को धक्का देकर लोगों के साथ घर में जा घुसा। इंदू देवी का आरोप है कि एक माह बाद ही बेटी की शादी है, इसके लिए जेवरात और कपड़ो की खरीदारी कर घर में रखी थी। हमलावर घर में आनंद को ढूंढते हुए बाक्स खोलकर सारा समान छिटते हुए जेवरातों की लूटपाट किए। उधर, गांव में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को देख किसी ने 112 पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस के पहुंचते ही हमलावर भाग निकले। गांव में हुए बवाल से अन्य ग्रामीण दहशत में है। इंदू देवी ने थाने पहुंच तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच–पड़ताल कर रही है। एसओ दिग्विजय सिंह ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

धीरे–धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा देश –मंजू सिंह

संवाददाता–गोण्डा। महाराजा देवी बक्स सिंह इंटर कॉलेज में सेवा पखवाड़ा विकसित भारत के उपलक्ष में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवधेश कुमार सिंह मंजू सिंह सदस्य विधान परिषद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ रामचंद्र रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य व माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने आए हुए अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र देकर किया । मुख्य अतिथि एमएलसी मंजू सिंह ने कहा कि भारत के आत्मनिर्भर बनने का सपना तभी साकार होगा जब उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया हो। हमें चीन की तर्ज पर सस्ते दर पर उत्पाद करना होगा साथ ही साथ हमें विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्पादों को आगे लाना होगा। आज देश सेना के उपयोगी सामान हथियार बनाना, विमान बनाने के साथ–साथ खाद्यान्न एवं अन्य मामले में आत्म निर्भर बना हैं। हम अनाज दूसरे देश को भी दे रहे हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में सर्वांगीण विकास कर रहा है।

छोटी बड़ी सभी शिकायतों का हो समय से हो निस्तारण–डीएम

संवाददाता–श्रावस्ती। सभी थानों में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें डीएम व एसपी ने लोगों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण का निर्देश दिया। इस दौरान कुल 33 शिकायती पत्र मिले।

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की अध्यक्षता में कोतवाली भिनगा में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। जिसमें डीएम व एसपी ने लोगों की शिकायत सुनी। डीएम ने कहा कि थाना दिवस में आने वाले फरियादियों से नम्र व्यवहार किया जाए और गम्भीरतापूर्वक उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण किया जाए। समाधान दिवस में आई भूमि विवादों की शिकायतों को सूचीबद्ध कर राजस्व व पुलिस की गठित टीम मौके पर जाकर बिना किसी पक्षपात के शिकायतों का निस्तारण किया जाय। एसपी ने सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेकर तुरंत मौके पर जाकर प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की जाय। शिकायत के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता को फोन के माध्यम से सूचित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत निस्तारण में लापरवाही की शिकायत मिली तो संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम व एसपी ने सिरसिया थाने में भी लोगों की शिकायत सुनकर निस्तारण का निर्देश दिया।

ब्लाक प्रमुख सेमरियावां सहित 55 क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर मुकदमा दर्ज

संवाददाता–संतकबीरनगर। सेमरियावां ब्लाक की प्रमुख मजहरुन्निशा व अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन देने वाली क्षेत्र पंचायत सदस्य हाजरा खातून सहित 55 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के विरुद्ध गुरुवार की देर रात गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। यह मुकदमा अविश्वास के लिए लगाए गए शपथ पत्र को गुमराह कर बनाए जाने और एक ही मामले में दो शपथ पत्र में अलग–अलग बयान देने के कारण किया गया। जांच में 50 क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ ही प्रमुख, प्रमुख का विरोध करने वाली सदस्य व अविश्वास प्रस्ताव के पत्र पर दस्तखत करने वाले तीन अन्य सदस्य दोषी पाए गए हैं। मुकदमे की मुख्य अभियुक्त हाजरा खातून पूर्व प्रमुख महमूद खान की पत्नी हैं और पूर्व विधान सभा प्रत्याशी मशहूर आलम चौधरी की बहू हैं।

प्रभारी डीपीआरओ ने राजेश कुमार अपने तहरीर में लिखा है कि ब्लाक प्रमुख सेमरियावां के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए हाजरा खातून, संगीता देवी, मनीष कुमार तथा बदरुन्निशा ने संयुक्त हस्ताक्षर से 27 जुलाई 2024 को प्रार्थना पत्र डाक के जरिए प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में कुल 91 सदस्यों के शपथ पत्र दिए गए। इसके साथ ही ब्लाक प्रमुख मजहरुन्निशा ने 30 जुलाई व पांच अगस्त 2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अविश्वास प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर, निशानी अंगूठा बनाए जाने का आरोप लगाया। इसके संबंध में 75 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। सेमरियावां में कुल 121 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं लेकिन दोनों पक्षों से 166 शपथ पत्र दिए गए। जब इसकी जांच की गई तो 50 क्षेत्र पंचायतों के शपथ पत्र ऐसे मिले जिन्होंने दोनों पक्ष से अलग–अलग शपथ पत्र दिया था। जिलाधिकारी ने इसकी जांच सीडीओ जयकेश त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित कमेटी को सौंपा। जांच में सभी 50 क्षेत्र पंचायत सदस्य को अपना बयान अंकित कराए जाने के लिए बुलाया गया। इसमें 48 क्षेत्र पंचायत सदस्य सीडीओ कार्यालय में उपस्थित कर अपना बयान दर्ज कराया। सभी के बयान प्रश्नोत्तरी के रूप में दर्ज किए गए। 48 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 39 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हाजरा खातून के पक्ष में अपना बयान दिया। चार क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव से सम्बन्धित शपथ पत्र पर किए गए हस्ताक्षर को फर्जी बताया। तीन क्षेत्र पंचायत सदस्य ने अविश्वास के पक्ष में प्रस्तुत शपथ पत्र पर अपना हस्ताक्षर न होना बताया। एक क्षेत्र पंचायत सदस्य ने अविश्वास के पक्ष में शपथ पत्र पर किए गए हस्ताक्षर को सही बताया। दूसरे वाले पर बिना बताए हस्ताक्षर कराया जाना बताया। एक क्षेत्र पंचायत सदस्य ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र पर अपना हस्ताक्षर करना बताया। इससे स्पष्ट है कि हाजरा खातून पत्नी महमूद आलम सहित अन्य व ब्लाक प्रमुख मजहरुन्निशा व 50 क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा प्रतिरूपण कर बेइमानी पूर्ण तरीके से धोखा देकर शपथ पत्र तैयार किया गया। एक शपथ पत्र से भिन्न दूसरे शपथ पत्र में गलत कथन किया गया है जो अपराधजनित है। प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी ने मामले में दोषी हाजरा खातून, ब्लाक प्रमुख मजहरुन्निशा, प्रस्ताव पर दस्तखत करने वाले तीन सदस्य व अन्य 50 सदस्यों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग किया। पुलिस ने साक्ष्य और तहरीर के आधार पर प्रमुख सहित 55 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। दुधारा पुलिस ने सभी 55 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319(2), 318(2), 318(4), 338, 336(2), 336(3), 340(2) के तहत केस दर्ज किया है।

दुधारा पुलिस ने मुख्य अभियुक्त हाजरा खातून पत्नी महमूद आलम के साथ ही ब्लाक प्रमुख मजहरुन्निशा, संगीता देवी, मनीष कुमार, बदरुन्निशा, रीता, रोहित कुमार, शनि देवल, अमृतलाल, पंचराम, राहुल कुमार, सकीना खातून, रंगीलाल, साधना, अजय प्रकाश, धर्मात्मा प्रसाद, शान्ति देवी, मिथलेश, फखरुल इस्लाम, धर्मेन्द्र कुमार, मोहम्मद सलीम, सुभावती, गुलाम हुसेन, नौशाद अली, जितेन्द्र कुमार, इबारत हुसेन, मीरा, प्रभावती, बबीता, रुकसाना खातून, बदरुन्निशा, इजहार अहमद, नजरुल अहमद, नीतू, बबिता, रविन्द्र कुमार, पवनारी देवी, साधना, फिरोज अहमद, अलीमुन्निशा, पंकज कुमार, बदरे आलम, इम्तियाज अहमद, बहादुर प्रसाद, आतिफा खातून, एबाद अहमद, राधिका देवी, मीना देवी, मोहम्मद महबूब, रमेश प्रसाद, खुशनुमा खातून, शमा अदनान, अर्चना, रामदास, रामकुमार का नाम शामिल है। हाजार खातून व कुछ अन्य सदस्यों के द्वारा डाक के जरिए अविश्वास के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसके बाद ब्लाक प्रमुख सेमरियावां ने 75 सदस्यों के साथ यह शपथ पत्र दिया कि वे उनके साथ हैं। सेमरियावां में कुल 121 सदस्य हैं, लेकिन शपथ पत्र 166 प्राप्त हुए। इसके बाद शपथ पत्रों की जांच हुई तो 50 ऐसे मिले जिन्होंने दोनों तरफ से शपथ पत्र दिया था। हालांकि टेक्निकल कारण से अविश्वास प्रस्ताव का प्रार्थना पत्र निरस्त हो गया था। इसके बाद हाजरा खातून ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया। शपथ पत्रों की जांच और सदस्यों के बयान में यह साबित हुआ कि कूटरचित तरीके से शपथ पत्र दिए गए हैं। इस कारण मुकदमा दर्ज कराया गया है।

हत्या के प्रयास के मामले में जेल हूं साहब, जमानत करा दीजिए

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिला जज अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह के पहल पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव सदस्यों के साथ जिला कारागार में पहुंचे। उन्होंने बंदी समस्या–समाधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बंदियों के समस्या से रूबरू होकर उसके निदान के प्रति उन्हें आश्वस्त किया। इस दौरान एक बंदी ने कहा कि मुझे हत्या के प्रयास के झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया है, मेरी जमानत करा दीजिए।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला कारागार में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के द्वारा बंदी समस्या–समाधान दिवस का आयोजन होता है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ताओं के द्वारा जिला कारागार में निरुद्ध कैदियों से मिलकर उनकी समस्या को जानकर उनके समाधान के लिए बेहतर प्रयास किया जाता है। शुक्रवार को लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव अपने सहयोगियों के साथ जिला कारागार के प्रत्येक बैरक में पहुंचकर कैदियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रत्येक कैदियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके मुकदमों में की जा रही पैरवी के बारे में पूछताछ की। उनके समस्या के त्वरित समाधान के लिए आश्वस्त किया। कोतवाली खलीलाबाद के बरदहिया बाजार निवासी मो. वकील ने कहा कि वह बीते फरवरी से हत्या के प्रयास के झूठे मुकदमें में कारागार में निरुद्ध हैं। उन्हें अपने मुकदमें के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है।

वहीं गड़सरपार गांव निवासी शकील ने कहा कि उनकी जमानत यहां से खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल न हो पाने के कारण जमानत नहीं हो पा रहा है। बखिरा थाना क्षेत्र के औघड़ टोला गांव निवासी छोटू गिरी ने कहा कि अवैध मादक पदार्थ रखने के जुर्म में झूठा फंसा दिया गया है। उसने भी जमानत कराने के लिए गुहार लगाई है। अंबेडकरनगर जिले के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के सहजोरा गांव निवासी मो. अरशद ने कहा कि उसकी जमानत हो गई है, फिर भी वह जेल से रिहा नहीं हो पा रहा है।

चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल संजीव कुमार पांडेय, असिस्टेंट मो. दानिश व प्रज्ञा श्रीवास्तव को बंदियों के समस्या को नोट कराते हुए उनके समस्याओं के शीघ्र निस्तारण कराए जाने के लिए आश्वस्त किया है। इस दौरान डिप्टी जेलर कमलनयन सिंह, गीता रानी, हरिकेश कुमार, जेल पैरालीगल वालंटियर पंकज समेत अन्य सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे।

निस्तारण की व्यावहारिक योजना पर हो अमल

ज्ञानेन्द्र रावत

पराली जलाने से हुए प्रदूषण से निपटने के दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। यह समस्या हर साल और विकराल होती चली जा रही है। सरकारें इस बाबत तब होश में आती हैं जब इस समस्या के चलते वायु प्रदूषण में बेतहाशा बढ़ोतरी से लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। पराली जलाने की घटनाओं में हुई कई गुणा बढ़ोतरी हालात की विकरालता का जीता–जागता सबूत है। धान की कटाई के रफ्तार पकड़ने के साथ ही पराली जलाने की घटनाओं में दैनंदिन होती बढ़ोतरी को खतरा माना जाना चाहिए। पराली जलाने से हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी अंचल, हरियाणा, पंजाब और किसी हद तक राजस्थान का सीमांत क्षेत्र सितम्बर से दिसम्बर के आखिर तक भयावह स्तर तक प्रभावित रहता है। ये महीने इन क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत बनकर आते हैं। इन राज्यों की सरकारों द्वारा इसे रोकने की दिशा में किए गये सारे प्रयास, अभियान और किसानों को जागरूक करने के सभी कदम बेमानी साबित हो जाते हैं। विडम्बना यह है कि यह सब तब होता है जबकि पराली जलाने पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बाबत गंभीर चिंता जाहिर कर चुकी है कि यह कैसा प्रबंधन है कि प्रतिबंध के बावजूद राज्यों में पराली जलायी जा रही है। हालात इस बात के सबूत हैं कि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम की अवहेलना हुई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग इस पर नियंत्रण कायम करने में नाकाम रहा है। क्योंकि एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिली है कि आयोग ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम के तहत एक भी दंडात्मक कार्रवाई की हो। हालात तो यही इशारा करते हैं कि पराली जलाने के खिलाफ निषेधात्मक निर्देश केवल कागजों तक ही सीमित रहे हैं। गौरतलब है कि राजधानी क्षेत्र में दुनिया के दस फीसदी अस्थमा से पीड़ित लोग रहते हैं। नतीजतन पहले से ही अस्थमा से परेशान लोगों के लिए बढ़ता वायु प्रदूषण जानलेवा बन जाता है। वैसे भी मौसम में आ रहे बदलाव के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर वहीं, पराली जलाये जाने से पीएम के स्तर में बढ़ोतरी चिंताजनक है। बीते 5 सालों के आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने के 75 फीसदी मामले अकेले पंजाब में ही हुए हैं। इस बार पंजाब में धान की कटाई के बाद 200 लाख टन पराली बचेगी, जबकि राज्य का लक्ष्य 19.52 लाख टन पराली के प्रबंधन का ही है। जाहिर है शेष पराली प्रबंधन के अभाव में जलाई ही जायेगी। ऐसे हालात में एसोचेम का कहना सही है कि स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना केन्द्र, राज्य, समाज और लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें हम विफल रहे हैं। खासतौर पर जब सर्दियों में आसमान धुंध और विषाक्त गैसों से घिरा होता है, के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे साल के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए एक समन्वित कार्य योजना बनायी जाये। गौरतलब है कि बीते साल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि पड़ोसी राज्यों के किसानों द्वारा पराली जलाये जाने से हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस दौरान वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस पर लगाम लगाई जाये और पराली से कंपोस्ट खाद बनाये जाने का आदेश दिया जाये। ऐसा करने से जहां खाद बनाने से बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर, किसान इस खाद का उपयोग कर बेहतर और रसायनविहीन पैदावार हासिल कर सकेंगे। चूंकि, मनरेगा पंचायत स्तर की सरकारी योजना है, इसलिए खाद बनाने की प्रक्रिया को मनरेगा से जोड़ा जाये। लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। बेशक, वायु प्रदूषण में पराली की अहम भूमिका है, लेकिन सड़कों की धूल, फैले कूड़े, वाहनों की धूल और बायोमास का भी नकारात्मक रोल होना है। इससे वातावरण में ज़हर के कॉकटेल का निर्माण होता है। वातावरण में सबसे अधिक घातक अजैविक एयरोसेल का निर्माण, बिजलीघरों, उद्योगों, ट्रैफिक से निकलने वाले सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन आक्साइड तथा कृषि कार्य से पैदा होने वाले अमोनिया के मेल से होता है। दरअसल, 23 फीसदी वायु प्रदूषण की वजह यह कॉकटेल ही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण, धुंध का 20 फीसदी उत्सर्जन दिल्ली के वाहनों से, 60 फीसदी दिल्ली के बाहर के वाहनों से तथा 20 फीसदी के आसपास बायोमास जलाने से होता है। आस्ट्रिया स्थित इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फार एप्लायड सिस्टम एनालीसिस और नीरी के शोध के अनुसार दिल्ली में प्रदूषित हवा के लिए 40 फीसदी दिल्लीवासी और 60 फीसदी पड़ोसी राज्य जिम्मेदार हैं। डब्ल्यूएचओ शोध–अध्ययन के अनुसार देश की हवा दिनोंदिन ज़हरीली होती जा रही है। इसलिए पराली जलाने पर किसानों को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए सरकारी प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता पूरी तरह जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण की समस्या किसी युद्ध की विभीषिका की आशंका से कम नहीं है। पराली जलाने से हुए प्रदूषण से निपटने के दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। यह समस्या हर साल और विकराल होती चली जा रही है। सरकारें इस बाबत तब होश में आती हैं जब इस समस्या के चलते वायु प्रदूषण में बेतहाशा बढ़ोतरी से लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। पराली जलाने की घटनाओं में हुई कई गुणा बढ़ोतरी हालात की विकरालता का जीता–जागता सबूत है। धान की कटाई के रफ्तार पकड़ने के साथ ही पराली जलाने की घटनाओं में दैनंदिन होती बढ़ोतरी को खतरा माना जाना चाहिए। पराली जलाने से हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी अंचल, हरियाणा, पंजाब और किसी हद तक राजस्थान का सीमांत क्षेत्र सितम्बर से दिसम्बर के आखिर तक भयावह स्तर तक प्रभावित रहता है। ये महीने इन क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत बनकर आते हैं। इन राज्यों की सरकारों द्वारा इसे रोकने की दिशा में किए गये सारे प्रयास, अभियान और किसानों को जागरूक करने के सभी कदम बेमानी साबित हो जाते हैं।विडम्बना यह है कि यह सब तब होता है जबकि पराली जलाने पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बाबत गंभीर चिंता जाहिर कर चुकी है कि यह कैसा प्रबंधन है कि प्रतिबंध के बावजूद राज्यों में पराली जलायी जा रही है। हालात इस बात के सबूत हैं कि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम की अवहेलना हुई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग इस पर नियंत्रण कायम करने में नाकाम रहा है। क्योंकि एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिली है कि आयोग ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम के तहत एक भी दंडात्मक कार्रवाई की हो। हालात तो यही इशारा करते हैं कि पराली जलाने के खिलाफ निषेधात्मक निर्देश केवल कागजों तक ही सीमित रहे हैं।गौरतलब है कि राजधानी क्षेत्र में दुनिया के दस फीसदी अस्थमा से पीड़ित लोग रहते हैं। नतीजतन पहले से ही अस्थमा से परेशान लोगों के लिए बढ़ता वायु प्रदूषण जानलेवा बन जाता है। वैसे भी मौसम में आ रहे बदलाव के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर वहीं, पराली जलाये जाने से पीएम के स्तर में बढ़ोतरी चिंताजनक है। बीते 5 सालों के आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने के 75 फीसदी मामले अकेले पंजाब में ही हुए हैं। इस बार पंजाब में धान की कटाई के बाद 200 लाख टन पराली बचेगी, जबकि राज्य का लक्ष्य 19.52 लाख टन पराली के प्रबंधन का ही है। जाहिर है शेष पराली प्रबंधन के अभाव में जलाई ही जायेगी। ऐसे हालात में एसोचेम का कहना सही है कि स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना केन्द्र, राज्य, समाज और लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें हम विफल रहे हैं। खासतौर पर जब सर्दियों में आसमान धुंध और विषाक्त गैसों से घिरा होता है, के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे साल के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए एक समन्वित कार्य योजना बनायी जाये। गौरतलब है कि बीते साल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि पड़ोसी राज्यों के किसानों द्वारा पराली जलाये जाने से हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस दौरान वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस पर लगाम लगाई जाये और पराली से कंपोस्ट खाद बनाये जाने का आदेश दिया जाये। ऐसा करने से जहां खाद बनाने से बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर, किसान इस खाद का उपयोग कर बेहतर और रसायनविहीन पैदावार हासिल कर सकेंगे। चूंकि, मनरेगा पंचायत स्तर की सरकारी योजना है, इसलिए खाद बनाने की प्रक्रिया को मनरेगा से जोड़ा जाये। लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। बेशक, वायु प्रदूषण में पराली की अहम भूमिका है, लेकिन सड़कों की धूल, फैले कूड़े, वाहनों की धूल और बायोमास का भी नकारात्मक रोल होना है। इससे वातावरण में ज़हर के कॉकटेल का निर्माण होता है। वातावरण में सबसे अधिक घातक अजैविक एयरोसेल का निर्माण, बिजलीघरों, उद्योगों, ट्रैफिक से निकलने वाले सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन आक्साइड तथा कृषि कार्य से पैदा होने वाले अमोनिया के मेल से होता है। दरअसल, 23 फीसदी वायु प्रदूषण की वजह यह कॉकटेल ही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण, धुंध का 20 फीसदी उत्सर्जन दिल्ली के वाहनों से, 60 फीसदी दिल्ली के बाहर के वाहनों से तथा 20 फीसदी के आसपास बायोमास जलाने से होता है। आस्ट्रिया स्थित इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फार एप्लायड सिस्टम एनालीसिस और नीरी के शोध के अनुसार दिल्ली में प्रदूषित हवा के लिए 40 फीसदी दिल्लीवासी और 60 फीसदी पड़ोसी राज्य जिम्मेदार हैं। डब्ल्यूएचओ शोध–अध्ययन के अनुसार देश की हवा दिनोंदिन ज़हरीली होती जा रही है। इसलिए पराली जलाने पर किसानों को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए सरकारी प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता पूरी तरह जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण की समस्या किसी युद्ध की विभीषिका की आशंका से कम नहीं है।

नाश्ते में शामिल करें हल्के व हेल्दी विकल्प

हम सब जानते हैं कि नाश्ता हमारी रोजमर्रा की सेहत के लिए न सिर्फ जरूरी होता है बल्कि इसका पौष्टिक होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक पौष्टिक नाश्ते के चलते ही हमारे कामकाजी दिन की उत्साहपूर्ण शुरुआत होती है। अगर नाश्ता अच्छे से किया जाए और यह पौष्टिक हो तो हम न सिर्फ ऊर्जा से लबालब रहते हैं बल्कि काम में हमारा मन भी लगता है। क्योंकि पौष्टिक और भरपूर नाश्ता करने से एकाग्रता बनती है, याद्दाश्त बेहतर होती है और बीमार कम पड़ने तथा बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण का खतरा भी कम रहता है। वहीं नाश्ता करने से वजन बढ़ता नहीं है, उल्टे मोटापे की आशंकाएं कम होती हैं। इस तरह देखें तो हमारे दिनभर के फूड में नाश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अकसर ट्रेंड व लोकप्रियता के नाम पर बल्कि कहना चाहिए, विज्ञापनों के प्रभाव में आकर हम पौष्टिक नाश्ता चुनने की बजाय स्वादिष्ट और खतरनाक नाश्ता चुनने की गलती कर बैठते हैं। जानिये कौन–कौन से ऐसे बेहद लोकप्रिय नाश्ते हैं, जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक हैं। आधे से ज्यादा भारत में सुबह नाश्ते के तौरपर तले हुए परांठों के खाने का चलन है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में तो परांठे के साथ चाय पीने का भी जबर्दस्त चलन है, जो परांठे को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। क्योंकि परांठे सैचुरेटिड फैट और चाय में मिल्क फैट होने के कारण इससे कोलेस्ट्रोल बढ़ता है। चाय–परांठे का नाश्ता करने से पेट में एसिड बनता है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को यह नाश्ता करने के बाद एसिडिटी की समस्या होती है। इससे लिवर को नुकसान होता है। शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। सुबह परांठे का नाश्ता करने के कारण पोषक तत्वों का शरीर भरपूर अवशोषण नहीं कर पाता, खासकर जब हम चाय के साथ परांठा खाते हैं। आप अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं तो परांठे को नाश्ते के रूप में खाने का मोह छोड़ दें। लेकिन अगर परांठा आपकी मजबूरी हो तो इसे पौष्टिक बनाकर खाएं। इसमें हरी सब्जियां भरकर भरवां पराठा खाएं, तो ये कम नुकसानदायक होते हैं। मल्टीग्रेन आटे के भरवां परांठे खाएं। साथ ही परांठों को तलें नहीं बल्कि बहुत कम देसी घी या मक्खन में पराठा बनाएं। ब्रेड और ब्रेकरी आइटमतले परांठों की ही तरह जो लोग व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड से बनने वाले तरह–तरह के व्यंजन नाश्ते में लेते हैं, वे भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आजकल विज्ञापनों के जरिये जोरशोर से व्हाइट ब्रेड की जगह होल ग्रेन ब्रेड को सभी तरह के खतरों से अलग और बेहद स्वास्थ्यकारी बताने का चलन है, लेकिन यह बात सही नहीं है। सच तो यह है कि होल ग्रेन या ब्राउन ब्रेड के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। किसी भी तरह की ब्रेड को अगर हम नियमित रूप से नाश्ते के तौरपर खाते हैं तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस से पीड़ित हो सकते हैं जिससे जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। नियमित ब्रेड खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है। ब्रेड में एमाइलोपेक्टिन ए होता है,

स्मार्ट बनेगी विश्वविद्यालय चौराहा से छात्रसंघ वाली सड़क

गोरखपुर। छात्रसंघ चौराहे से विश्वविद्यालय चौराहा वाली सड़क भी अब स्मार्ट बनेगी। नगर निगम इस सड़क को स्मार्ट रोड के तौर पर बनाने जा रहा है। यहां पर पैदल यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए फुटपाथ, हरियाली और पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। चुनाव बाद नगर निगम इसके लिए टेंडर जारी करेगा।

विश्वविद्यालय चौराहा से छात्रसंघ तक रोड के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए 11 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है। पहले यह काम लोक निर्माण विभाग को कराना था, लेकिन अब इसके लिए नगर निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद नगर निगम इसके लिए टेंडर जारी करेगा। टेंडर के बाद छह महीने के अंदर इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा।

दोनों तरफ बनेगा फुटपाथ

विश्वविद्यालय चौराहा से छात्रसंघ चौराहे तक 860 मीटर लंबी सड़क जल्द ही चौड़ी हो जाएगी। इसके दोनों तरफ नाले को आरसीसी बनाया जाएगा, साथ ही इसे ढककर फुटपाथ बनाया जाएगा। बिजली के खंभे व ट्रांसफार्मर शिफ्ट किए जाएंगे। इसके अलावा फुटपाथ को कुछ इस तरह बनाया जाएगा कि उसमें दो पहिया वाहन पार्क हो सकें। लोगों के बैठने के लिए बेंच की भी व्यवस्था की जाएगी। सड़क किनारे ड्रेनेज सिस्टम भी बनेगा ताकि नाले की सफाई में कोई समस्या न आए।

नहीं काटे जाएंगे एक भी पेड़

सड़क चौड़ीकरण और सुदंरीकरण के दौरान रास्ते में लगे एक भी पेड़ काटे नहीं जाएंगे। बल्कि काम पूरा होने के बाद इस रास्ते में और भी पेड़ लगाए जाएंगे ताकि यहां हरियाली बढ़ सके। इसके अलावा रोड के दोनों किनारे सुंदर लाइट लगाई जाएंगी।

विश्वविद्यालय चौराहा से छात्रसंघ वाली सड़क को स्मार्ट रोड के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसमें इसका चौड़ीकरण, दोनों तरफ पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ और हरियाली की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। चुनाव के बाद टेंडर जारी कर दिया जाएगा।

सिद्धार्थनगर से आए तेंदुए को उसके प्राकृतिक वास में छोड़ा

गोरखपुर। गोरखपुर। सिद्धार्थनगर के इटवा से रेस्क्यू कर गोरखपुर चिड़ियाघर लाए गए तेंदुए को बुधवार को सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग के शिवपुर रेंज में उसके प्राकृतिक वास में छोड़ दिया गया।

प्राणि उद्यान के पशु चिकित्साधिकारी डॉ. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव संजय श्रीवास्तव के निर्देशन में तेंदुए का इलाज चल रहा था। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे उसके प्राकृतिक वास में छोड़ने का निर्णय लिया गया। संजय श्रीवास्तव ने तेंदुए को सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के शिवपुर रेंज में छोड़ने के लिए डीएफओ सिद्धार्थनगर और सोहगीबरवा को निर्देशित किया।

इसके बाद तेंदुए को ट्रक से रेस्क्यू टीम के साथ डॉ. योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्राणि उद्यान के निदेशक विकास यादव ने रवाना किया। डॉ. योगेश ने बताया कि टीम दोपहर तीन बजे शिवपुर रेंज के घने जंगल में पहुंची। वहां पूरी सावधानी और व्यवस्था के बाद तेंदुए को उसके प्राकृतिक वास में अवमुक्त किया गया। तेंदुए को अवमुक्त करने में प्रभागीय वन अधिकारी सिद्धार्थनगर पुष्प कुमार सहित अन्य अधिकारी–कर्मचरियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

बता दें कि, सिद्धार्थनगर के इटवा इलाके के हटवा गांव में 29 अप्रैल को सोमवार को तेंदुआ घुस गया। गांव में उसने कुछ लोगों पर हमला भी कर दिया। बाद में कुछ ग्रामीणों ने लाठी–डंडों से तेंदुए पर हमला बोल दिया। इसमें उसे गंभीर चोटें आईं। गोरखपुर चिड़ियाघर से पहुंची टीम ने वन विभाग के साथ मिलकर शाम तक तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया। देर रात उसे इलाज के लिए शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान लाया गया। करीब एक हफ्ते तक चले इलाज के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया।

गोरखपुर में खुला खाता...दो ने किया नामांकन

गोरखपुर। लोकसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में खाता खुल गया। अल हिंद पार्टी के राम प्रसाद और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राधेश्याम सेहरा ने पर्चा दाखिल किया। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से एक भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा।

सुबह 11 बजे से एडीएम एफआर और एडीएम सीआरओ कोर्ट में सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर एक बजे नामांकन करने अल हिंद पार्टी के राम प्रसाद पहुंचे। एडीएम के कोर्ट से रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम कैंपियरगंज रोहित मौर्य सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ज्वाइंट मजिस्ट्रेटध्एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी की मौजूदगी में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद दोपहर दो बजे राधेश्याम सेहरा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दूसरी ओर बांसगांव से कोई प्रत्याशी नामांकन करने नहीं पहुंचा। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर संसदीय सीट से अशोक अग्रहरि, प्रेम प्रकाश, हरीश त्रिपाठी, साहबजादा, रमाकांत, सोनू राय, विजय भारती और नित्यानंद ने पर्चे लिए। कुल 15 सेट पर्चे लिए गए। इसी प्रकार बांसगांव लोकसभा से रामा और राकेश कुमार सिद्धार्थ ने पर्चे लिए।

एम्स में सात माह में हुई 650 मरीजों की फेको विधि से सर्जरी

गोरखपुर। मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सबसे सफल फेको विधि से एम्स में हर दिन ऑपरेशन किया जा रहा है। बीते साल अक्तूबर में यहां सेंचुरियन गोल्ड फेको मशीन लगी और अब तक इसकी सहायता से करीब 650 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफलता हो चुका है।

एम्स के नेत्र रोग विभाग की डॉ. अलका त्रिपाठी, डॉ. ऋचा अग्रवाल, डॉ. नेहा सिंह और डॉ. अमित ने बताया कि आंखों के ऑपरेशन के लिए फेको मशीन का प्रयोग अब तेजी से होने लगा है। इस मशीन के जरिए छोटा चीरा लगाकर कुछ मिनटों में ही ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

छोटा चीरा होने के कारण मरीज को कुछ ही घंटों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। जबकि पुरानी विधि में ऑपरेशन काफी जटिल होता था। मरीज को कम से कम आठ दिन तक अस्पताल में रुकना पड़ता था। यहां सख्त मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, माइक्रो कॉर्निया, कोलोबोमा आदि का भी ऑपरेशन हो रहा है। एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. जीके पाल ने कहा कि यह सुविधा गोरखपुर और आसपास के जिलों में कम ही जगह उपलब्ध है। इस विधि से ऑपरेशन काफी महंगा होता है, जबकि एम्स में बहुत ही कम खर्च में सारी सुविधाएं मिल जाती हैं।

परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की होगी अऑनलाइन उपस्थिति

गोरखपुर। एक तरफ अभी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी ही दुरुस्त नहीं हो पाई है। वहीं, दूसरी तरफ बच्चों की उपस्थिति और एमडीएम की व्यवस्था को ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है। विभाग जुलाई माह से बच्चों की उपस्थिति और मिड डे मील को पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करने जा रहा है। इसके लिए लिए जून माह में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

अब तक सभी विद्यालयों में टैबलेट का वितरण भी नहीं किया जा सका है। प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में कहीं एक तो कहीं दो टैबलेट दे दिए गए हैं। सिम व हर माह रिचार्ज के लिए भी कंपोजिट ग्रांट के वितरण से भी शिक्षक खुश नहीं है। वहीं, जुलाई माह से विद्यालयों के दो रजिस्टर ऑनलाइन हो जाएगे। शेष को भी जल्द ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।बता दें कि अभी तक जिले में 4113 टैबलेट का वितरण विद्यालयों में किया गया है। शेष विद्यालयों में भी विभाग जल्द ही टैबलेट भेजने की तैयारी कर रहा है।

हवाओं की तेजी से बेसअर हुई धूप, न्यूनतम तापमान गिरा

गोरखपुर। मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। कभी बदली राहत दे रही है तो कभी धूप परेशानी भी बढ़ा रही है। मगर बुधवार को तेज धूप के बाद भी गर्मी ने लोगों को परेशान नहीं किया। तेज हवाओं की वजह से धूप की तेजी कम रही और लोगों को गर्मी का अहसास कम हुआ। मौसम विभाग के जिम्मेदारों की मानें तो आने वाले दो–तीन दिन अभी ऐसा ही मौसम रहेगा। बदली और धूप के साथ तेज हवाएं चलेंगी। वहीं इस दौरान बारिश की भी संभावना है। ऐसे में तापमान में भी स्थिरता बनी रहेगी। विभाग ने 12 मई के बाद आसमान साफ होने के साथ ही तापमान में वृद्धि की आशंका जताई है।

मौसम की उठा–पटक के बीच बुधवार को सुबह से ही मौसम सुहवाना रहा। मंगलवार को बदली और बारिश का असर बुधवार को भी नजर आया और ठंडी हवा के झोंकों से लोगों को राहत मिली। हालांकि इस बीच धूप भी खिली, लेकिन तेज हवाओं ने इसे बेअसर कर दिया। दिन भर धूप के बाद भी लोगों को ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई। मौसम के इस रुख की वजह से अधिकतम तापमान में मामूली का उछाल देखने को मिला और यह 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, यह मई में रहने वाले सामान्य तापमान के मुकाबले 5.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इतना ही नहीं, मंगलवार को हुई बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और यह 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस था। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। बुधवार को जिले में कहीं पर भी बारिश नहीं हुई। मौसम वैज्ञानिक जय प्रकाश गुप्ता की मानें तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके बाद रविवार को भी बारिश के आसार हैं। 12 मई से आसमान साफ होने की उम्मीद है, जिसके बाद अधिकतम तापमान में इजाफा होगा।

अक्षय तृतीया पर होगे धार्मिक अनुष्ठान व मांगलिक कार्य

गोरखपुर। अक्षय तृतीया के विशेष मुहूर्त पर मंदिरों व घरों में धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जबकि बिना लगन के ही मांगलिक कार्य भी होंगे। ज्योतिर्विदों के अनुसार अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त में होगी। इन दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, गुरु व शुक्र दोनों ग्रहों के अस्त होने के कारण लोग वैवाहिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, जबकि मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई सहित अन्य कार्य आयोजित किए जा रहे हैं।

अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर लोग गहने सहित अन्य नए सामानों की खरीदारी करेंगे। मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस दिन जप, तप और दान पुण्य का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन अर्जित किए गए पुण्यों का क्षय नहीं होता है। 10 मई को अक्षय तृतीया है, इसलिए रजिस्ट्री विभाग में भी तैयारी की गई है, जो जोड़े वहां पहुंच जाएं, उनको कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दिया जाए।

आचार्य नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अक्षय तृतीया पर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम किया जा सकता है। हालांकि, गुरु और शुक्र अस्त होने के कारण लोगों ने अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर वैवाहिक कार्यक्रम नहीं करने का निर्णय किया है। सगाई और गृह प्रवेश सहित अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। क्योंकि, दो माह तक गृह प्रवेश के मुहूर्त नहीं है। अक्षय तृतीया पर यदि कोई वैवाहिक रस्में पूरी करता है तो वह अनुचित नहीं होगा। गृहस्थ जीवन के लिए शुभकारी शुक्र एवं मंगलकारी गुरु अस्त हैं, इसलिए पुरोहितों ने पंचांग के अनुसार लोगों को अक्षय तृतीया पर वैवाहिक कार्यक्रम करने की सलाह नहीं दी है। पूर्वांचल में इस तिथि में विवाह करने का ज्यादा प्रचलन नहीं है, जबकि लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान करने की तैयारी की है।

भ्रूण लिंग जांच रोकेंगी दो समितियां

गोरखपुर। भ्रूण के लिंग जांच पर रोक लगाने के लिए मंडलीय निगरानी समितियों का गठन कर दिया गया है। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डॉ. बीएम राव और डॉ. अरुण गर्ग के नेतृत्व में दो समितियों का गठन किया है। दोनों समितियां अवैध हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथोलाजी सेंटर के संचालन की रोकथाम के साथ ही शिकायतों का निस्तारण भी करेंगी।

यह कार्रवाई अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकरण परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ के निर्देश पर की गई है। गोरखपुर और कुशीनगर जनपद के लिए संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डॉ. बीएम राव और महराजगंज व देवरिया के लिए संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डॉ. अरुण गर्ग की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। टीम जनपद के पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों का जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक तीन माह पर निरीक्षण की स्थिति की भी समीक्षा करेगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, शक्ति शंकर द्वारा फाईन आफसेट प्रिंटर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्शीपुर, जनपद–गोरखपुर से मुद्रित कराकर, मुहल्ला–द्वितीय तल पुष्पांजलि काम्प्लेक्स शाही मार्केट, गोलघर, जनपद–गोरखपुर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक :
शक्ति शंकर
मो नं.
7233999001
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र गोरखपुर न्यायालय होगा।